KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

Planning in India
(भारत में योजना)

History of Planning / योजना का इतिहास

- Economic planning was first explored and adopted by the former Soviet Union, with their first five-year plan commencing from 1928.
- India's planning first came from an engineer-administrator, M. Visvervaraya in his book titled "Planned Economy in India".
- In 1938, the Indian National Congress headed by Pandit J.L. Nehru appointed the National Planning Committee (NPC) to prepare a plan for economic development.
- Various Industrialists came together in 1944 and drafted a joint proposal for setting up a planned economy in India. It is famously known as the Bombay Plan.

- आर्थिक नियोजन को पहली बार पूर्व सोवियत संघ द्वारा खोज़ा और अपनाया गया था, उनकी पहली पंचवर्षीय योजना 1928 से शुरू हुई थी।
- भारत की योजना सबसे पहले एक इंजीनियर-प्रशासक, एम. विश्ववरैया ने अपनी पुस्तक "प्लांड इकोनॉमी इन इंडिया" में लिखी थी।
- 1938 में, पंडित जे.एल. नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आर्थिक विकास की योजना तैयार करने के लिए राष्ट्रीय योजना समिति (एनपीसी) की नियुक्ति की।
- 1944 में विभिन्न उदयोगपति एक साथ आए और भारत में एक नियोजित अर्थव्यवस्था स्थापित करने के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया। इसे बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है।

History of Planning / योजना का इतिहास

- In 1944, Sriman Narayan Agarwal authored The Gandhian Plan, in which he emphasized the promotion of small unit production and agriculture, based on Gandhian economic ideas.
- M N Roy drafted the People's Plan in 1945.
- Jaiprakash Narayan designed the Sarvodaya Plan in 1950. This plan was inspired by Vinoba Bhave's Sarvodaya Idea and Gandhian Plan.
- After independence, the Planning Commission was set up by the Government of India in March 1950 as non constitutional and non statutory body.
- The Planning Commission was replaced by a think tank called NITI AAYOG in 2015.

- 1944 में, श्रीमन नारायण अग्रवाल ने गांधीवादी योजना लिखी, जिसमें उन्होंने गांधीवादी आर्थिक विचारों के आधार पर छोटी इकाई उत्पादन और कृषि को बढ़ावा देने पर जोर दिया।
- एम एन रॉय ने 1945 में पीपुल्स प्लान का मसौदा तैयार किया था।
- जयप्रकाश नारायण ने 1950 में सर्वोदय योजना तैयार की थी। यह योजना विनोबा भावे के सर्वोदय विचार और गांधीवादी योजना से प्रेरित थी।
- आज़ादी के बाद मार्च 1950 में भारत सरकार द्वारा गैर संवैधानिक और गैर वैधानिक निकाय के रूप में योजना आयोग की स्थापना की गई थी।
- योजना आयोग को 2015 में NITI AAYOG नामक थिंक टैंक द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।

First Five-Year Plan (1951-56) / प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-56)

- It was presented by the first Indian Prime Minister, Jawaharlal Nehru to the Parliament of India.
- It was based on the Harrod Domar Model and emphasised increasing savings.
- It mainly addressed the agrarian sector, including investment in dams and irrigation. Example - Huge allocations were made for Bhakhra Nangal Dam.
- Integral Coach Factory (ICF) established in 1955.
- By the end of 1956, five Indian Institutes of Technology were established.
- The target growth rate was 2.1% and the achieved growth rate was 3.6%.

- प्रथम पंचवर्षीय योजना में भारत में आर्थिक विकास पर जोर दिया गया।
- इसे प्रथम भारतीय प्रधान मंत्री, जवाहरलाल नेहरू दवारा भारत की संसद में प्रस्तुत किया गेया था।
- यह हैरोड डोमर मॉडल पर आधारित था और बचत बढ़ाने पर जोर देता था।
- इसने मुख्य रूप से बांधों और सिंचाई में निवेश सहित कृषि क्षेत्र को संबोधित किया। उदाहरण - भाखड़ा नागल बांध के लिए भारी आवंटन किया गया।
- इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (ICF) की स्थापना 1955 में हुई।
- 1956 के अंत तक, पाँच भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किये गये।
- लक्ष्य वृद्धि दर 2.1% थी और प्राप्त वृद्धि दर 3.6% थी।

Second Five Year Plan (1956-61) / द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956-61)

- The Second Five year Plan stressed rapid industrialisation and the public sector.
- It was drafted and planned under the leadership of P.C Mahalanobis.
- The government imposed tariffs on imports to protect domestic industries under this plan.
- Iron and steel industries at Durgapur, Bhilai, and Rourkela, Chemical fertilizers plant at Sindri, Rail engine factory at Chittaranjan, Factory of railway bogies at Perambur, Ship building factory at Vishakhapattanam.
- Jawaharlal Nehru inaugurated Panchayati Raj at Nagaur on October 2, 1959.

- दूसरी पंचवर्षीय योजना में तेजी से औद्योगीकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर जोर दिया गया।
- इसका मसौदा और योजना पी.सी. महालनोबिस के नेतृत्व में बनाई गई थी।
- सरकार ने इस योजना के तहत घरेलू उद्योगों की सुरक्षा के लिए आयात पर शुल्क लगाया।
- दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला में लौह और इस्पात उद्योग, सिंदरी में रासायनिक उर्वरक संयंत्र, चित्तरंजन में रेल इंजन कारखाना, पेरंबर में रेलवे बोगियों का कारखाना, विशाखापत्तनम में जहाज निर्माण कारखाना।
- जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर, 1959 को नागौर में पंचायती का उद्घाटन किया।

Third Five Year Plan (1961-66) / तीसरी पंचवर्षीय योजना (1961-66)

- The focus was on agriculture and improvement in the production of wheat.
- The third Five Year Plan (1961 – 1966) is known as Gadgil Yojana.
- India's Third Five Year Plan was the first to incorporate the objective of self-reliance.
- This indicated a miserable failure of the Third Plan, and the government had to declare "Plan Holidays" (1966-67, 1967-68, and 1968-69).
- The Sino-Indian War and the Indo-Pak War were the primary causes of the plan holidays.

- फोकस कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार पर था।
- तीसरी पंचवर्षीय योजना (1961-1966) को गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है।
- भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को शामिल करने वाली पहली योजना थी।
- इससे तीसरी योजना की बुरी विफलता का संकेत मिला और सरकार को "योजना अवकाश" (1966-67, 1967-68 और 1968-69) घोषित करना पड़ा।
- चीन-भारत युद्ध और भारत-पाक युद्ध, योजना छुट्टियों के प्राथमिक कारण थे।

Fourth Five-Year Plan: (1969-74) / चौथी पंचवर्षीय योजना: (1969-74)

- It was introduced under the Prime Ministership of Indira Gandhi and attempted to correct the previous failures.
- Focus : Growth with stability and progress towards self-reliance.
- The government nationalised 14 major Indian Banks and the Green Revolution boosted agriculture.
- Monopolistic and Restrictive Trade Practices Act (MRTP Act)- 1969
- Establishment of Buffer Stock.
- Operation Flood - 1970
- The Drought Prone Area Programme was also launched.

- इसे इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में पेश किया गया था और पिछली विफलताओं को सुधारने का प्रयास किया गया था।
- फोकस : स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की ओर प्रगति।
- सरकार ने 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और हरित क्रांति ने कृषि को बढ़ावा दिया।
- एकाधिकारवादी और प्रतिबंधात्मक व्यापार आचरण अधिनियम - 1969
- बफर स्टॉक की स्थापना.
- ऑपरेशन फ्लड - 1970
- सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम भी शुरू किया गया।

Fifth Five-Year Plan (1974-78) / पाँचवीं पंचवर्षीय योजना (1974-78)

- It laid stress on increasing employment and poverty alleviation (garibi hatao).
- In 1975, the Electricity Supply Act was amended.
- The Indian National Highway System was introduced.
- India successfully conducted its first nuclear test (Smiling Buddha) in the year 1974.
- The Minimum Needs Programme introduced in the first year of this plan, aimed to provide basic minimum needs. MNP was prepared by D.P. Dhar.
- Indira Gandhi had then President Fakhruddin Ali Ahmed impose Emergency every six months for a period of 21 months from June 25, 1975 to March 21, 1977.
- In 1978, the newly elected Morarji Desai government rejected this plan.

- इसमें रोजगार बढ़ाने और गरीबी उन्मूलन (गरीबी हटाओ) पर जोर दिया गया।
- 1975 में, विद्युत आपूर्ति अधिनियम में संशोधन किया गया।
- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई।
- भारत द्वारा अपना पहला परमाणु परीक्षण (मुस्कुराते हुए बुद्ध) वर्ष 1974 में सफलतापूर्वक किया गया
- इस योजना के पहले वर्ष में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य बुनियादी न्यूनतम आवश्यकताएं प्रदान करना था। एमएनपी डी.पी. धर द्वारा तैयार किया गया था।
- इंदिरा गांधी ने तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक 21 महीने की अवधि के लिए हर छह महीने में आपातकाल लगाया था।
- 1978 में नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने इस योजना को अस्वीकार कर दिया।

PM :- मोरारजी देसाई

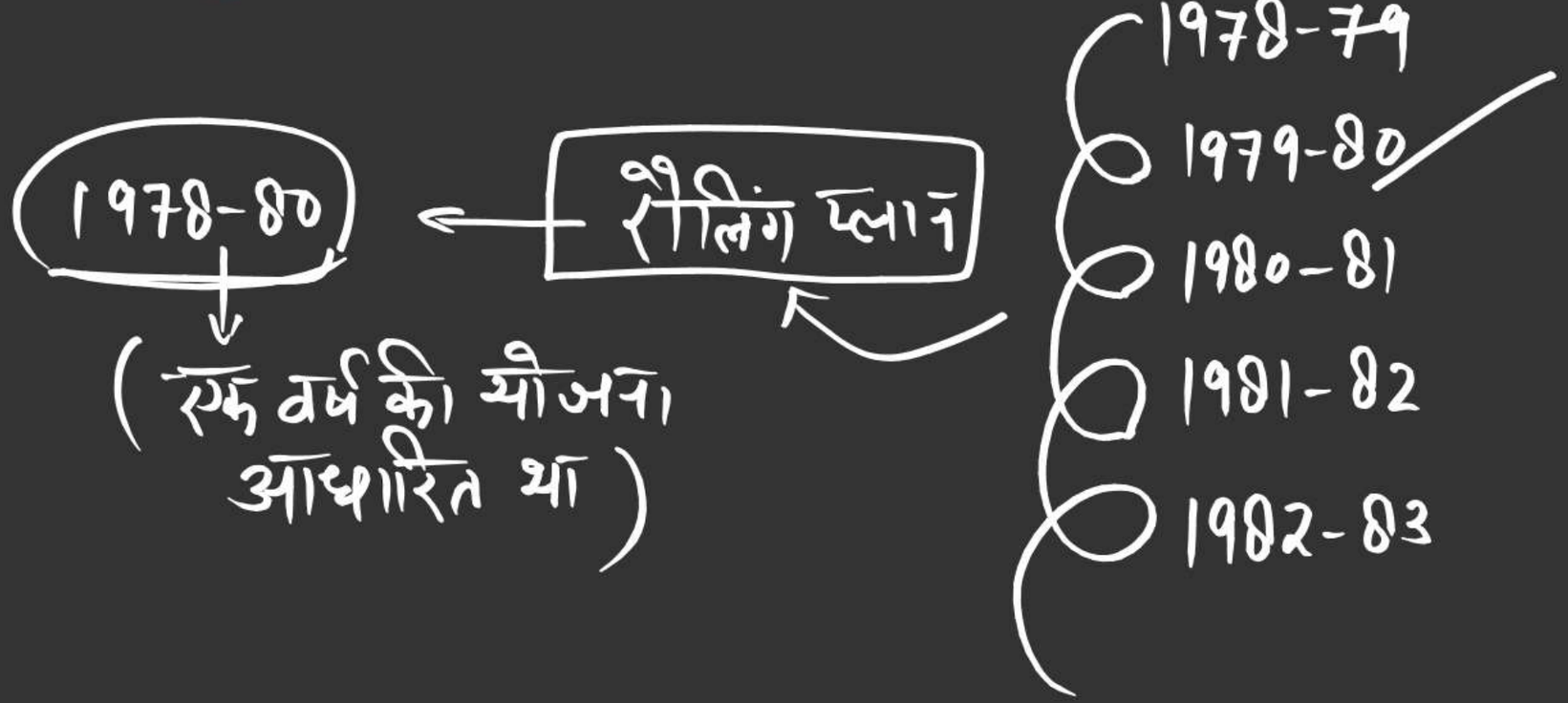

1978-80 ← रौलिंग प्लान

(एक वर्ष की योजना आधारित था)

1978-79
1979-80
1980-81
1981-82
1982-83

Rolling Plan (1978-80) / रोलिंग योजना (1978-80)

- This was a period of instability. The Janata Party government rejected the fifth five-year Plan and introduced a new Sixth Five-Year Plan. This, in turn, was rejected by the Indian National Congress in 1980 upon Indira Gandhi's re-election.

- यह अस्थिरता का दौर था. जनता पार्टी सरकार ने पाँचवीं पंचवर्षीय योजना को अस्वीकार कर दिया और एक नई छठी पंचवर्षीय योजना पेश की। बदले में, 1980 में इंदिरा गांधी के दोबारा चुने जाने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसे अस्वीकार कर दिया।

- A rolling plan is one in which the effectiveness of the plan is evaluated annually and a new plan is created the following year based on this evaluation. As a result, throughout this plan, both the allocation and the targets are updated.

- रोलिंग योजना वह है जिसमें योजना की प्रभावशीलता का वार्षिक मूल्यांकन किया जाता है और इस मूल्यांकन के आधार पर अगले वर्ष एक नई योजना बनाई जाती है। परिणामस्वरूप, इस पूरी योजना में, आवंटन और लक्ष्य दोनों अद्यतन किए जाते हैं।

Sixth Five Year Plan (1980-85) / छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85)

- It underlined the beginning of economic liberation by eliminating price controls.
- To prevent overpopulation, family planning was introduced.
- 1980 - Nationalization of 6 Banks
- 1982 - EXIM Bank
- 1982 - National Bank for Agriculture and Rural Development was established.

For generate Employment :

- Integrated Rural Development Programme (IRDP)
- Development of women and children in Rural Areas (DWCRA)

- इसने मूल्य नियंत्रण को समाप्त करके आर्थिक मुक्ति की शुरुआत को रेखांकित किया।
- अधिक जनसंख्या को रोकने के लिए परिवार नियोजन की शुरुआत की गई।
- 1980 - 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण
- 1982 - एक्ज़िम बैंक
- 1982 - राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई।

रोजगार उत्पन्न करने के लिए:

- एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आईआरडीपी)
- ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास (DWCRA)

Sixth Five Year Plan (1980-85) / छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85)

- Training of Rural Youth for Self Employment (TRYSEM)
- National Rural Employment Programme (NREP)
- Rural Landless Employment Guarantee Programme (RLEGP)

- स्व-रोज़गार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण (ट्राइसेम)
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एनआरईपी)
- ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (आरएलईजीपी)

PM = राजीव गाँधी

Seventh Five Year Plan (1985-90) / सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90)

- This plan was led by the Prime Ministership of Rajiv Gandhi.
- It laid stress on improving Industrial productivity levels through the use of technology.
- 1986 - Consumer Protection Act (Now 2019)
- 1986 - Speed Post
- 1987 - Tribal Co-operative Marketing Development Federation of India (TRIFED)
- 1988 - SEBI
- 1989 - Jawahar Rozgar Yojana

- इस योजना का नेतृत्व राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में किया गया था।
- इसने प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से औद्योगिक उत्पादकता स्तर में सुधार पर जोर दिया।
- 1986 - उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (अब 2019)
- 1986 - स्पीड पोस्ट
- 1987 - भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ (ट्राइफेड)
- 1988 - सेबी
- 1989 - जवाहर रोज़गार योजना

1991 = आर्थिक सुधार / नई आर्थिक नीति / LPG मॉडल

आर्थिक सुधारों का जनक = P.V. नरसिम्हन रॉव (P.M)

वित्त मंत्री = मनमोहन सिंह ।

1990 = आर्थिक संकट

1990-92 → Annual Plan (वार्षिक योजना)

LPG मॉडल

- (L) Liberalization (उदारीकरण)
- (P) Privatization (निजीकरण)
- (G) Globalization (वैश्वीकरण)

Annual Plans (1990-92) / वार्षिक योजनाएँ (1990-92)

- The Eight Five Year Plan was not introduced in 1990 and the following years 1990-91 and 1991-92 were treated as Annual Plans.
- This was largely because of the economic instability.
- India faced a crisis of foreign exchange reserves during this time.
- 1991 - Indian rupee was Devalued
- Liberalisation, Privatisation, Globalisation (LPG) was introduced in India to grapple with the problem of the economy under prime minister P.V Narasimha Rao.

- आठवीं पंचवर्षीय योजना 1990 में शुरू नहीं की गई थी और अगले वर्ष 1990-91 और 1991-92 को वार्षिक योजना के रूप में माना गया था।
- इसका मुख्य कारण आर्थिक अस्थिरता थी।
- इस दौरान भारत को विदेशी मुद्रा भंडार के संकट का सामना करना पड़ा।
- 1991 - भारतीय रुपये का अवमूल्यन किया गया
- प्रधान मंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव के तहत अर्थव्यवस्था की समस्या से निपटने के लिए भारत में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण (एलपीजी) की शुरुआत की गई थी।

Eighth Five Year Plan (1992-97) / आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97)

- The Eighth Plan promoted the modernisation of Industries.
- India became a member of the World Trade Organisation on 1 January 1995.
- The goals were to control population growth, reduce poverty, generate employment, strengthen the development of infrastructure, manage tourism, focus on human resource development etc.
- It also laid emphasis on involving the Panchayats and Nagar Palikas through decentralisation.

- आठवीं योजना ने उद्योगों के आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया।
- 1 जनवरी 1995 को भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना।
- लक्ष्य जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना, गरीबी कम करना, रोजगार पैदा करना, बुनियादी ढांचे के विकास को मजबूत करना, पर्यटन का प्रबंधन करना, मानव संसाधन विकास पर ध्यान केंद्रित करना आदि थे।
- इसमें विकेंद्रीकरण के माध्यम से पंचायतों और नगर पालिकाओं को शामिल करने पर भी जोर दिया गया।

Ninth Five Year Plan (1997-2002) / नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002)

- It marked India's fifty years since Independence and Atal Bihari Vajpayee led the prime ministership.
- It offered support for social spheres to achieve complete elimination of poverty.
- 1998 - Pokhran Test (Operation Shakti)
- 1998 - National Highways Development Project (NHDP)
- 1999 - Kargil War
- 2001-2002 : sarva shiksha abhiyan
- Dec, 2000 - The Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana

25 Dec = सुशासन दिवस

- भारत की आज़ादी के पचास साल पूरे हुए और अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्रित्व का नेतृत्व किया।
- इसने गरीबी का पूर्ण उन्मूलन हासिल करने के लिए सामाजिक क्षेत्रों में समर्थन की पेशकश की।
- 1998 - पोखरण परीक्षण (ऑपरेशन शक्ति)
- 1998 - राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एनएचडीपी)
- 1999 - कारगिल युद्ध
- 2001-2002: सर्व शिक्षा अभियान
- 25 दिसंबर, 2000 - प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

Tenth Five Year Plan (2002-07) / दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07)

- The features of this plan were to promote inclusive growth and equitable development.
- 2005 - Mahatma Gandhi National. Rural Employment Guarantee Act
- It aimed at reducing the poverty by half and creating employment for 80 million people. Further, it aimed to reduce regional inequalities.
- It also emphasised reducing the gender gaps in the field of education and wage rates by 2007.

- इस योजना की विशेषताएं समावेशी विकास और समान विकास को बढ़ावा देना थीं।
- 2005 - महात्मा गांधी राष्ट्रीय। ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
- इसका उददेश्य गरीबी को आधा करना और 80 मिलियन लोगों के लिए रोजगार पैदा करना था। इसके अलावा, इसका उद्देश्य क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना था।
- इसमें 2007 तक शिक्षा और वेतन दरों के क्षेत्र में लैंगिक अंतर को कम करने पर भी जोर दिया गया।

Eleventh Five Year Plan (2007-2012) / ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012)

- The Eleventh Plan was significant in its aim to increase enrolment in higher education and focused on distant education as well as IT institutes.
- The Right to Education Act was introduced in 2009, and came into effect in 2010, making education free and compulsory for children aged between 6-14 years.
- Its main theme was rapid and more inclusive growth.
- It is aimed at environmental sustainability and reduction in gender inequality.
- 2011 - Swabhiman Scheme
- The focus was also laid on providing clean drinking water for all by 2009.

- ग्यारहवीं योजना उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के अपने उददेश्य में महत्वपूर्ण थी और दूरस्थ शिक्षा के साथ-साथ आईटी संस्थानों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया था।
- शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में पेश किया गया था, और 2010 में लागू हुआ, जिससे 6-14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा मुफ्त और अनिवार्य हो गई।
- इसका मुख्य विषय तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास था।
- इसका उददेश्य पर्यावरणीय स्थिरता और लैंगिक असमानता में कमी लाना है।
- 2011 - स्वाभिमान योजना
- 2009 तक सभी के लिए स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया।

Twelfth Five Year Plan (2012-17) / बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-17)

- The last Five Year Plan had "Faster, More Inclusive and Sustainable Growth" as its theme.
- 2013 - National Food Security Act
- 2014 - Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY)
- 2015 - Make in India , Skill India , Digital India
- 2015 - Foreign Trade Policy
- It also aimed at removing the gender and social gap in admissions at school and improved access to higher education.
- Further, it aspired to enhance the green cover by 1 million hectares each year and to create new opportunities in the non-farming sector.

- पिछली पंचवर्षीय योजना का विषय "तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास" था।
- 2013 - राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम
- 2014 - प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई)
- 2015 - मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया
- 2015 - विदेश व्यापार नीति
- इसका उद्देश्य स्कूल में प्रवेश में लिंग और सामाजिक अंतर को दूर करना और उच्च शिक्षा तक पहुंच में सुधार करना भी है।
- इसके अलावा, इसकी आकांक्षा हर साल 1 मिलियन हेक्टेयर हरित आवरण को बढ़ाने और गैर-कृषि क्षेत्र में नए अवसर पैदा करने की थी।

National Development Council (NDC) / राष्ट्रीय विकास परिषद

- The National Development Council (NDC) is India's apex authority for approving five-year plans.
- National Development Council was set up in August 6, 1952.
- The Prime Minister presides over the National Development Council.
- The National Development Council (NDC) is headquartered in New Delhi.

- राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) पंचवर्षीय योजनाओं को मंजूरी देने के लिए भारत का सर्वोच्च प्राधिकरण है।
- राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त, 1952 में की गई थी।
- प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता करते हैं।
- राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) का मुख्यालय नई दिल्ली में है।

NITI Aayog / नीति आयोग

- **Full Name** : National Institution for Transforming India
- Established : 1 Jan, 2015
- **HQ** – New Delhi
- **Chairperson** : Shri Narendra Modi, Hon'ble Prime Minister
- **Vice Chairperson** : Shri Suman Bery
- **Full-Time Members** : Shri V.K. Saraswat, Prof. Ramesh Chand, Dr. V. K. Paul , Arvind Virmani

- पूरा नाम: नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया
- स्थापना: 1 जनवरी, 2015
- मुख्यालय – नई दिल्ली
- अध्यक्ष: श्री नरेंद्र मोदी, माननीय प्रधान मंत्री
- उपाध्यक्ष: श्री सुमन बेरी
- पूर्णकालिक सदस्य: श्री वी.के. सारस्वत, प्रो. रमेश चंद, डॉ. वी.के. पॉल, अरविंद विरमानी

V.R, Ramesh, Arvind

NITI Aayog / नीति आयोग

- **Ex-officio Members :**
  - Shri Raj Nath Singh, Minister of Defence
  - Shri Amit Shah, Minister of Home Affairs and Minister of Cooperation
  - Smt. Nirmala Sitharaman, Minister of Finance and Minister of Corporate Affairs
  - Shri Shivraj Singh Chouhan, Minister of Agriculture and Farmers' Welfare

- **Chief Executive Officer :** B. V. R. Subrahmanyam

- पदेन सदस्य :

-श्री राज नाथ सिंह, रक्षा मंत्री

- श्री अमित शाह, गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री

-श्रीमती निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री

-श्री शिवराज सिंह चौहान, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री

- मुख्य कार्यकारी अधिकारी: बी. वी. आर. सुब्रमण्यम

Governing Council : ① राज्यों के C.M.
शासी परिषद ② केन्द्र शासित (UT) के उपराज्यपाल

* Vision Document = 15 वर्ष

Medium-Term 7y 7y

Short-Term Agenda = 3y 3y 3y 3y 3y

NITI Aayog / नीति आयोग

- **Governing Council :** The Governing Council of NITI Aayog, comprising Chief Ministers of all the States and Union Territories with legislatures and Lt Governors of other Union Territories.

- गवर्निंग काउंसिल: नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल, जिसमें सभी राज्यों और विधानसभाओं वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल हैं।

- The Niti Aayog has come out with three documents — 3-year action agenda, 7-year medium-term strategy paper and 15-year vision document.

- नीति आयोग तीन दस्तावेज़ लेकर आया है - 3-वर्षीय कार्य एजेंडा, 7-वर्षीय मध्यम अवधि की रणनीति दस्तावेज़ और 15-वर्षीय विज़न दस्तावेज़।

Think-Tank

KHAN GLOBAL STUDIES

The Most Trusted Learning Platform

THANKS FOR WATCHING